करण सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1474, 2010)

28 मई 2013

[डॉ बी. एस. चौहान और दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति]

भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 302 हत्या निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि अभिनिर्धारित किया गया: हत्या के उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा एकरूप वृतांत अभियोजन मामले को स्वतंत्र गवाह द्वारा भी समर्थन दिया गया प्रार्थी जो कि, प्रभावशाली व्यक्ति था उसको झूंठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।अनुसंधान

दूषित अनुसंधान में अभिनिर्धारित किया गया: दूषित अनुसंधान आपराधिक न्याय की विफलता का कारण बनती है, और इस प्रकार एक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देती है। कानून के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अनुसंधान विवेकपूर्ण, निष्पक्ष पारदर्शी और शीघ्र

होनी चाहिए। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के तहत आवश्यक है भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद, 19, 20 और 21

अभियोजन कहानी पर दूषित अनुसंधान का प्रभाव अभिनिर्धारित किया गया अनुसंधान में प्रत्येक विसंगति के परिणामस्वरूप बरी नहीं किया जा सकता. जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह बेईमानीपूर्वक थी या निर्देशित अनुसंधान थी या आरोपी के बचाव में गंभीरतापूर्वक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो

अपीलकर्ता अभियुक्त पर एक महिला की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब पीडब्लू-3 अपनी बेटी पीडब्लू-4 के साथ अपने खेत की सिंचाई कर रही थी, तो उसने अपनी बेटी (मृतिका) की रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि अपीलकर्ता ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर मृतक के गले में रस्सी डाल दी थी और उसे खेत में घसीट रहा था; और अपीलकर्ता का मृतक के साथ 47,000 रूपये के भुगतान के संबंध में विवाद था अपीलकर्ता द्वारा प्रतिफल के रूप में 47,000 रूपये के विवाद को लेकर अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था और सह-अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और डिफॉल्ट क्लॉज के साथ 25000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया

गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इसलिए, वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

1.1. अपीलकर्ता द्वारा भैंस की बिक्री के लिए बिक्री प्रतिफल के रूप में 47,000/- रुपये की राशि का भुगतान न करने के संबंध में महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा एकरूप कथन किए गए हैं। घटनाओं का यह वृतांत भी PW.3 और PW.4 द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से पूरी तरह से साबित है। बचाव पक्ष द्वारा 47,000/- रुपये की राशि का भुगतान न करने के आरोप को गलत साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी स्थापित होता है कि घटना से 2-3 दिन पहले अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलकर्ता ने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। घटनाओं का ऐसा वृतांत PW.8, जो एक स्वतंत्र गवाह है, के साक्ष्य से और भी पुख्ता हो जाता है। बचाव पक्ष द्वारा किसी भी गवाह से ठीक से जिरह नहीं की गई। हालांकि दोनों अदालतों ने जांच के तरीके के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की है, उन्होंने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उचित सजा सुनाई है। [पैरा 6 से 8] [1175-डी, एफ, जी; 1176-बी-सी)

1.2. पी डब्लयू 3 और 4 की मैदान में मौजूदगी संदेहास्पद नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक कृषक के लिए यह सामान्य बात है कि जब भी उसकी सिंचाई की बारी आती है, वह सिंचाई का कार्य करता है। बचाव पक्ष ने पीडब्ल्यू 3 और 4 से भूमि की खेती के संबंध में, बटाई के नियमों और शर्तों के संबंध में, और यह भी कि भूमि की सिंचाई करना किसका कर्तव्य था, और सिंचाई के स्रोत और साधन क्या थे, इसके बारे में कोई और विवरण प्रस्तुत करना नहीं पूछा था।। [पैरा 9] [1176-ई-एफ]

1.3. निचली अदालतों ने ठीक ही माना कि आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह गांव का सरपंच था और एक प्रभावशाली व्यक्ति था; कि PW.8 एक स्वतंत्र गवाह था और उसकी गवाही की अवहेलना करने का कोई आधार नहीं था; और आबादी घटना स्थल से कुछ दूरी पर थी और इसलिए, मृतक और डी द्वारा बाद में पीडब्लू.3 द्वारा उठाया गया शोर और रोना किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। [पैरा 17] [1181-बी-डी]

1.4. बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई अन्य कहानी खारिज किए जाने योग्य हैं। उनका कहना था कि मृतक एक व्यभिचारिणी महिला थी और उसके कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे; उसकी माँ का अपमान (पीडब्लू.3) आदि अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते। कुछ व्यक्तियों और अपीलकर्ता के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

का कहानी, जिनके कहने पर पीडब्लू.3 एफ और पीडब्लू.4 ने इतने जघन्य अपराध का आरोप लगाया था, भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। [पैरा 8,10] [1176- सी: 1176-एच; 1177-ए]

2.1. किसी आपराधिक अपराध की अनुसंधान किसी भी आपत्तिजनक विशेषताओं या कमजोरियों से मुक्त होनी चाहिए जो शिकायतकर्ता या आरोपी के मन में यह आशंका पैदा कर सकती है कि अनुसंधान निष्पक्ष नहीं था और किसी गलत मकसद से किया गया हो सकता है अनुसंधान अधिकारी को किसी भी प्रकार की बदमाशी में शामिल नहीं होना चाहिए, या शिकायतकर्ता या आरोपी को परेशान नहीं करना चाहिए। उसका आचरण पूरी तरह से निष्पक्ष और अनुसंधान की वास्तविकता के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करना होना चाहिए। अनुसंधान अधिकारी, "न केवल साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए मौजूद है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम करेगा, बल्कि सच्चाई का वास्तविक वृतांत सामने लाने के लिए भी मौजूद है।" अनुसंधान एजेंसी की ओर से नैतिक आचरण अत्यंत आवश्यक है, और दुर्भावना या दोष के किसी भी आरोप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। [पैरा 12] [1177-सी-एफ]

राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। **एआईआर 1998 एससी 1850: 1998 (2) एससीआर 1097;** *अमर सिंह बनाम बलविंदर*

सिंह एवं अन्य। **एआईआर 2003 एससी 1164: 2003 (1) एससीआर 754;** *राम बाली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **एआईआर 2004 एससी 2329: 2004 (1) पूरक। एससीआर 195 पर आधारित किया।**

2.2. संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' जैसे शब्द व्यापक आयाम प्रदान करते हैं, जिसमें सभी प्रकार के अधिकार, विशेष रूप से भारत के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, और प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा निर्धारित. इस प्रकार अनुसंधान एजेंसियाँ निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता की संरक्षक हैं। इसलिए, अनुसंधान अधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए, हालांकि, साथ ही, किसी आरोपी व्यक्ति को अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक कि अदालतों द्वारा भी किसी अनुसंधान में हस्तक्षेप या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अनुसंधान एजेंसी को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से पूरी तरह बचना चाहिए, और अनुसंधान को आरोपी या शिकायतकर्ता की स्थिति की परवाह किए बिना समान तत्परता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि एक दूषित अनुसंधान निश्चित रूप से आपराधिक न्याय की विफलता का कारण बनती है, और इस प्रकार यह एक व्यक्ति को संविधान

के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अनुसंधान विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र होना चाहिए कानून के नियमों का अनुपालन, जैसा कि आवश्यक है संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21. [पैरा 12] [1177- सी-एफ]

बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य **(2010) 12 एससीसी 254: बी 2010 (10) एससीआर 651 - पर आधारित।**

2.3. अनुसंधान अधिकारी की ओर से की गई चूक, जहां अभियोजन पक्ष साक्ष्य, विशेष रूप से चश्मदीदों और अन्य गवाहों को जोड़कर किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल होता है, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा। इस कारण से कि अनुसंधान में मौजूद प्रत्येक विसंगति न्यायालय के मतानुसार इतना प्रभावपूर्ण नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से आरोपी को बरी कर दिया जाए, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अनुसंधान इस तरह से किया गया था कि इसे "बेईमान" करार दिया जाए। या दोषपूर्ण अनुसंधान", जो आरोपी को बरी कर देगा। इस प्रकार, जब तक कि अनुसंधान अधिकारियों की ओर से की गई चूक ऐसी न हो, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर उचित संदेह पैदा हो, या आरोपी के बचाव पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अदालत केवल आरोपी की दोषसिद्धि को

दूषित अनुसंधान के आधार पर रद्द नहीं करेगी। [पैरा 14] [1178-एफ-एच; 1179-बी-सी]

2.4. प्रकरण में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि PW.9, जिसने प्रारंभिक चरण में अनुसंधान की थी, ने कानून के अनुसार काम नहीं किया था और अपीलकर्ता का पक्ष लिया था। यही कारण है कि पुलिस अधिकारियों ने एक शिकायत पर अनुसंधान अधिकारी को बदल दिया, जिसने फिर जी अनुसंधान ठीक से की। इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस स्टेशन के SHO द्वारा की गई अनुचित अनुसंधान के संबंध में विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा कुछ गंभीर तथ्य दर्ज किए गए हैं। प्रशासन को बेहतर रूप से ज्ञात कारणों के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव से मामले की विधिसम्मत् जांच की जाकर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है, और कानून के अनुसार कार्यवाही करें. [पैरा 11 और 19] [1177-बी; 1181-जी-एच; 1182-ए-बी]

सोनाली मुखर्जी बनाम भारत संघ **(2010) 15 एससीसी 25: 2009 (14) एससीआर 858;** *मो. इमरान खान बनाम राज्य सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)* **(2011) 10 एससीसी 192: 2011 (15) एससीआर 1030;** *शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य।* **एआईआर 2011 एससी 1403: 2011 (4) एससीआर 312;** *गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य*

(2012) 9 एससीसी 532: 2012 (7) एससीआर 1033; *श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **एआईआर 2012 एससी 3539: 2012 (10) एससीआर 95;** *हीरालाल पांडे एवं अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य* **एआईआर 2012 एससी 2541: 2012 (3) एससीआर 1066 - पर आधार बनाया गया।**

दयाल सिंह और अन्य. बनाम उत्तरांचल राज्य **(2012) 8 एससीसी 263: 2012(10) एससीआर 157 संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ:

2010 (10) एससीआर 651	**पर आधारित**	**पैरा 12**
1998 (2) एससीआर 1097	**पर आधारित**	**पैरा 13**
2003 (1) एससीआर 754	**पर आधारित**	**पैरा 13**
2004 (1) पूरक एससीआर 195	**पर आधारित**	**पैरा 13**
2009 (14) एससीआर 858	**पर आधारित**	**पैरा 14**
2011 (15) एससीआर 1030	**पर आधारित**	**पैरा 14**
2011 (4) एससीआर 312	**पर आधारित**	**पैरा 14**
2012 (7) एससीआर 1033	**पर आधारित**	**पैरा 14**

2012 (10) एससीआर 95 **पर आधारित पैरा 14**

2012 (3) एससीआर 1066 **पर आधारित पैरा 14**

2012 (10) एससीआर 157 **पर आधारित पैरा 15**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1474, 2010

2007 की आपराधिक अपील संख्या 226-डीबी में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.02.2009 से

अपीलार्थी की ओर से - नीरज कुमार जैन, ऋषि मल्होत्रा, देवाशीष भरुका

प्रत्यर्थी की ओर से- मंजीत सिंह, एएजी, रमेश कुमार, कमल मोहन गुप्ता न्यायालय का निर्णय डीआर द्वारा सुनाया गया।

डॉ. बी.एस. चौहान, न्यायाधिपति 1. यह अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2007 की आपराधिक अपील संख्या 226-डीबी में दिनांक 6.2.2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय ने 8.9.2005 के सत्र परीक्षण संख्या 110 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8.2.2007 की पुष्टि की है, जिसके तहत

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। दंड संहिता 1860 (इसके बाद इसे 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), और उसे आजीवन कारावास और 25,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। इस तरह के जुर्माने का भुगतान न करने पर, उसे 3 साल की अवधि के लिए आरआई भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार इस अपील से उत्पन्न होने वाले तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार हैं: -

ए. 6-7.1.2005 की मध्यरात्रि में, मृतक राज की मां माया देवी (पीडब्लू 3) अपनी बेटी बिरमा (पीडब्लू 4) के साथ अपने खेत की सिंचाई कर रही थी। अपनी बेटी की चीख सुनकर राज. माया देवी और बीरमा मौके पर पहुंचे और देखा कि कालिया ने राज और करण सिंह को पकड़ लिया था, अपीलकर्ता ने उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी डाल दी थी और उसे खेतों में दूर तक खींच रहा था। माया देवी (पीडब्लू.3) ने काफी शोर मचाया लेकिन कोई मदद नहीं मिली और गला घोंटने के परिणामस्वरूप राज की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह माया देवी (पीडब्लू.3) अपने बेटे हरिओम (एक साधारण व्यक्ति) के साथ घटनास्थल पर गयीं। गेहूं के खेत में घसीटने के निशान थे। मृतक के गले पर चोट का निशान भी साफ दिख रहा था।

बी. माया देवी (पीडब्लू.3) रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ पुलिस अधिकारियों से हुई और उसने उन्हें घटना के बारे में बताया, जिसके आधार पर, पुलिस स्टेशन, सदर चरखी दादरी में आईपीसी की धारा 302/34 के तहत 7.1.2005 को एक एफआईआर दर्ज की गई।

सी. राज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. डॉ. यू.एस. दासोदिया (पीडब्लू.7) ने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और उसकी गर्दन पर एक निशान पाया। उनका मत है कि उसकी मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने के कारण हुई, जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। उनकी चोटों और मृत्यु के बीच समय का अंतर केवल कुछ मिनट था, और उनकी मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच भी 24 घंटे से भी कम समय था

डी. पुलिस ने माया देवी (पीडब्लू.3), बीरमा (पीडब्लू.4) के साथ-साथ अन्य लोगों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी करने के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सह-अभियुक्त कालिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

ई. अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता करण सिंह का मृतक राज के साथ एक भैंस की बिक्री के प्रतिफल के रूप में 47,000/-

रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने को लेकर कुछ विवाद था। मृतक राज. चूंकि अपीलकर्ता ने उक्त पैसे का भुगतान नहीं किया था, उसी को लेकर 3-4.1.2005 को उनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें अपीलकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के अनुक्रम में, अपीलकर्ता द्वारा राज की हत्या कर दी गई।

एफ. अभियोजन पक्ष ने माया देवी (पीडब्लू.3), बिरमा (पीडब्लू.4) और ओंकार सिंह (पीडब्लू.8) सहित कई गवाहों को परीक्षित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (इसके बाद 'सी.आर.पी.सी.' के रूप में संदर्भित) के तहत अभियुक्त-अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि पूर्व वर्णित है ।

इसलिए, यह अपील पेश की गई है।.

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज कुमार जैन ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में जांच दूषित थी। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान। घटना के कई महीनों के बाद दर्ज किया गया था। राज. मृतक एक ऐसी महिला थी जो अपने पति से इस कारण से अलग हो गई थी क्योंकि वह एक व्यभिचारिणी महिला थी और अपनी माँ और बहन से भी अलग रह रही थी। मृतक की मां माया देवी (पीडब्लू.3) का विशिष्ट मामला यह था कि वह अपनी बेटी के साथ

खेतों की सिंचाई करने गई थी, हालांकि अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया है कि कृषि भूमि एक खज़ान को दी गई थी, कृषि उपज (बटाई) के बंटवारे पर। मृतक की बहन बिरमा (पीडब्लू.4) ने गवाही दी है कि वे स्वयं जमीन पर खेती नहीं करते थे।

विचारण न्यायालय ने माया देवी (पीडब्लू.3) और बीरमा (पीडब्लू.4) द्वारा बताए गए गए घटनाओं के वृतांत पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में माना। अभियोजन का पूरा मामला असंभव है. अत: अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित एएजी, श्री मंजीत सिंह ने यह कहते हुए अपील का विरोध किया कि नीचे की अदालतों ने तथ्य के एकरूप निष्कर्ष दर्ज किए हैं। बचाव पक्ष ने जिरह में माया देवी (पीडब्लू.3) या बीरमा (पीडब्लू 4) से किसी की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में 47,000/- रुपये की राशि का भुगतान न करने के संबंध में कोई सवाल नहीं पूछा था। मृतक राज द्वारा अपीलकर्ता करण सिंह को भैंस, इस तथ्य के बावजूद कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि उक्त राशि का भुगतान न करने को लेकर विवाद हुआ था। मृतक और अपीलकर्ता के बीच उक्त राशि का भुगतान 3.1.2005 को किया गया। अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा, यह कथन ओंकार सिंह (पीडब्लू.8) के बयान से पुष्ट हुआ। इस घटना में

कि जांच के दौरान कुछ अनौचित्य हुआ था, वह केवल अपीलकर्ता के कहने पर हुआ था और वह भी पूरी तरह से उसके पक्ष में था और निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं था। अपीलकर्ता ने अपराध में इस्तेमाल की गई रस्सी को छिपाने के बारे में स्पष्ट बयान दिया है, लेकिन जांच अधिकारी ने उसे बरामद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा परस्पर की गई विपरीत रूप से दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. अपीलकर्ता द्वारा भैंस की बिक्री के लिए बिक्री प्रतिफल के रूप में 47,000/- रुपये की राशि का भुगतान न करने के संबंध में महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा एकरूप तथ्य पेश किए गए हैं। घटनाओं का यह वृतांत माया देवी (पीडब्लू.3) और बीरमा (पीडब्लू.4) द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से भी पूरी तरह से स्थापित है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में, बचाव पक्ष ने उक्त बयान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए माया देवी (पीडब्लू.3) या बीरमा (पीडब्लू.4) से कोई सवाल नहीं पूछा। केवल यह कहते हुए इनकार करना कि अपीलकर्ता द्वारा गलत होने का कथन करते हुए इंकार करने का तथ्य पर्याप्त नहीं है और अभियोजन पक्ष के मामले के उक्त हिस्से पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी स्थापित होता है कि घटना से 2-3 दिन

पहले अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलकर्ता ने मृतका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। ओंकार सिंह (पीडब्लू.8) के साक्ष्य से घटनाओं का ऐसा वृतांत और भी पुख्ता हो गया है।

7. ओंकार सिंह (पीडब्लू.8) एक स्वतंत्र गवाह है जिसने गवाही दी है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह एक दुकान से कुछ सब्जियां लाने गया था। आरोपी-अपीलकर्ता तब हरिजन बस्ती की ओर से वहां आया था, उसने पूछा कि राज (वेश्या) कहां गई थी, और कहा था कि वह उसे 2-3 दिन के अंदर मार डालेगा। आरोपी-अपीलार्थी के मृतक के साथ अवैध संबंध थे और उक्त समय आरोपी शराब के नशे में था।

8. इनमें से किसी भी गवाह से बचाव पक्ष द्वारा उचित रूप से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। हालांकि दोनों अदालतों ने अनुसंधान के तरीके के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उन्होंने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उचित सजा सुनाई है। बचाव पक्ष द्वारा कई में अन्य कहानी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक एक व्यभिचारिणी महिला थी और यही कारण था कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, वह गांव में बस गई थी और अलग रह रही थी घर। अपनी मां के घर से दूर, और यहां भी, उसके कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, आदि। इसी को लेकर पंचायत भी

हुई थी. और माया देवी (पीडब्लू.3) आदि को अपमानित किया गया था। जो भी हो, इस प्रकार का सिद्धांत अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।

9. जहां तक उक्त भूमि पर खेती करने का प्रश्न है, बचाव पक्ष ने PW.3 और 4 से भूमि की खेती के संबंध में, बटाई के नियमों और शर्तों के संबंध में और कोई विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा था, और साथ ही भूमि की सिंचाई करना किसका कर्तव्य था, और सिंचाई का स्रोत और साधन क्या थे, क्योंकि उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से आधी रात को कृषि क्षेत्रों में होने का दावा किया है। उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी सिंचाई की बारी आती है, तो प्रत्येक कृषक के लिए सिंचाई का कार्य करना सामान्य बात है।

10. चूंकि बचाव पक्ष ने इस संबंध में माया देवी (पीडब्लू.3) और बिरमा (पीडब्लू.4) से जिरह के दौरान कोई और सवाल नहीं पूछा है, इसलिए हम किसी भी तरह का लाभ देने की स्थिति में नहीं हैं। अपीलकर्ता को इन प्रश्नों के बारे में।कुछ अन्य व्यक्ति तथा याचिकाकर्ता के मध्य राजनीतिक दुश्मनी होने की कहानी, माया देवी (पीडब्लू.3) और बीरमा (पीडब्लू.4) ने किसके कहने पर इतने जघन्य अपराध का आरोप लगाया, यह विश्वसनीय नहीं है। अत: वे अस्वीकृत किये जाने योग्य हैं।

11. यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि राजेश कुमार, एसआई (पीडब्लू.9), जिन्होंने प्रारंभिक चरण में जांच की थी, ने कानून के अनुसार काम नहीं किया था और अपीलकर्ता का पक्ष लिया था। यही कारण है कि पुलिस अधिकारियों ने एक शिकायत पर अनुसंधान अधिकारी को बदल दिया, जिसने बाद में सही प्रकार से अनुसंधान किया।

12. किसी आपराधिक अपराध में अनुसंधान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक तत्वों से या कमियों से परे होना चाहिए जो शिकायतकर्ता या आरोपी के मन में यह आशंका पैदा कर सकती है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और किसी गलत उद्देश्य से की गई हो सकती है। जांच अधिकारी को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए, या शिकायतकर्ता या आरोपी को परेशान नहीं करना चाहिए। उसका आचरण पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और जांच की वास्तविकता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करना चाहिए। जांच अधिकारी, "न केवल साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए मौजूद है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम करेगा, बल्कि सच्चाई का वास्तविक वर्णन सामने लाने के लिए भी मौजूद है।" जांच एजेंसी की ओर से नैतिक आचरण अत्यंत आवश्यक है, और दुर्भावना या पूर्वाग्रह के किसी भी आरोप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' जैसे शब्द व्यापक आयाम प्रदान करते हैं,

जिसमें सभी प्रकार के अधिकार, विशेष रूप से भारत के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, और किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा विहित प्रक्रिया को अपनाए बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जाँच एजेंसियाँ निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता की संरक्षक हैं। इसलिए, जांच अधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, हालांकि, साथ ही, किसी आरोपी व्यक्ति को अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक कि अदालतों द्वारा भी किसी जांच में हस्तक्षेप या उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जांच एजेंसी को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से पूरी तरह बचना चाहिए, और जांच को समान तत्परता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए, भले ही आरोपी या शिकायतकर्ता की स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि एक दूषित अनुसंधान निश्चित रूप से आपराधिक न्याय की विफलता की ओर ले जाती है, और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी से वंचित कर देती है। इस प्रकार, कानून के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र होनी चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के तहत आवश्यक है। (द्वारा: बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2010) 12 एससीसी 254)।

13. *राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य,* एआईआर 1998 एससी 1850 में, इस न्यायालय ने कहा, कि यदि किसी सोची समझी या लापरवाही से की गई जांच, या किसी दोषपूर्ण जांच के परिणामस्वरूप हुई चूक या चूक को प्राथमिकता दी जाती है , लोगों का विश्वास और विश्वास न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी में, बल्कि न्याय प्रशासन में भी हिल जाएगा

इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा *अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य,* एआईआर 2003 एससी 1164 में दोहराया गया है।

इसके अलावा, *राम बाली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* एआईआर 2004 एससी 2329 में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जानबूझकर की गई दोषपूर्ण जांच, अभियोजन के द्वारा बताई गई घटनाओं का वृतांत विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।

14. अनुसंधान अधिकारी की ओर से की गई चूक, जहां अभियोजन पक्ष साक्ष्य, विशेष रूप से चश्मदीदों और अन्य गवाहों को जोड़कर किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल होता है, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा। केवल इस कारण से कि अनुसंधान में मौजूद प्रत्येक विसंगति न्यायालय की नजरों में इतनी

अहमियत नहीं रखती है कि यह आवश्यक रूप से अभियुक्त को दोषमुक्त कर सके, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि जांच इस तरह से की गई थी कि इसे "बेईमान या निर्देशित जांच" करार दिया जाए, जो आरोपी को बरी कर देगी। (देखें: *सोनाली मुखर्जी बनाम भारत संघ*, (2010) 15 एससीसी 25; *मो. इमरान खान बनाम राज्य सरकार (एनसीटी दिल्ली),* (2011) 10 एससीसी 192: *शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य*, एआईआर 2011 एससी 1403; *गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य,* (2012) 9 एससीसी 532: *श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,* एआईआर 2012 एससी 3539; और *हीरालाल पांडे एवं अन्य बनाम यूपी राज्य,* एआईआर 2012 एससी 2541)।

इस प्रकार, जब तक कि जांच संस्था के द्वारा छोड़ी गई कमियां इस प्रकार की हों वे अभियोजन के केस पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती हो या अभियुक्त के बचाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय दोषसिद्धि को केवल दूषित अनुसंधान के आधार पर रद्द नहीं करेगा।

15. इस न्यायालय द्वारा *दयाल सिंह एवं अन्य में बनाम उत्तरांचल राज्य*, (2012) 8 एससीसी 283, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ने जांच करने में कर्तव्य में लापरवाही या कदाचार के दोषी जांच अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। और

यह माना गया कि राज्य सीमा के कानून की अनदेखी करते हुए भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य है, और भले ही ऐसा अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया हो।

16. वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने पहले अनुसंधान अधिकारी, श्री राजेश कुमार द्वारा किए गए दूषित अनुसंधान के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों की विस्तृत जांच की है, और उच्च न्यायालय ने इस पर निम्नानुसार टिप्पणी की है :

"यह रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से स्थापित है कि एसआई राजेश कुमार ने जांच ठीक से नहीं की थी और वह अपीलकर्ता के पक्ष में इसका झुकाव था और इसलिए, मामले को खराब कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 19 में विस्तृत कारण दर्ज किए हैं, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता का पुलिस पर प्रभाव था। हम विचारण न्यायालय के उक्त तर्क से सहमत हैं जो विद्वान राज्य वकील द्वारा दिए गए तर्कों से भी स्पष्ट है, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है। जैसा कि जांच रिपोर्ट में बताया गया है, मृतक को घसीटने के निशान थे, लेकिन फिर भी एस.आई राजेश कुमार ने अपने द्वारा बनाये गये रफ साइट प्लान एक्स.पी-25 में उक्त निशानों को दर्शाया नहीं है. उन्होंने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के डॉग स्क्वायड या अपराध टीम की सेवाओं का भी लाभ नहीं उठाया। जिस दुकान में मृतक रहता था, उसका शटर भी टूटा हुआ था, लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने

इसकी फोटो खींचने की जहमत नहीं उठाई और न ही जांच कार्यवाही में कहीं भी इसका जिक्र किया। इसलिए, शिकायतकर्ता को अनुसंधान अधिकारी की चूक के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता एक विधवा है जिसकी सात बेटियां और केवल एक बेटा है, जो साधारण भी है। मृतिका भी तलाकशुदा थी और अपने पैतृक गांव में खेतों में बने घर (दुकान) में अकेली रहती थी.....शिकायतकर्ता माया देवी, जो मृतक की मां है, एक विधवा और अनपढ़ देहाती ग्रामीण है, जबकि मृतक तलाकशुदा था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और घटना के समय सरपंच था। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में ही अपीलकर्ता और उसके सह-अभियुक्त कालिया का नाम लिया। हालाँकि, एफआईआर में विकृत वृतांत दर्ज किया गया था और जब शिकायतकर्ता पक्ष को 26.1.2005 को एफआईआर की प्रति मिली (जैसा कि बिरमा देवी पीडब्लू 4 द्वारा बताया गया है), तो उन्हें इसकी जानकारी हुई और फिर उन्होंने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से संपर्क किया, जिन्होंने ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अपीलकर्ता विधान सभा सदस्यों के साथ एसपी से मिला था। इसके बाद, एसपी के बदलने के साथ, शिकायतकर्ता पक्ष ने फिर से नए एसपी से संपर्क किया और उसके बाद ही 18.2.2005 को माया देवी और बिरमा देवी के सही बयान दर्ज किए गए। अपीलकर्ता इतना प्रभावशाली था कि उसके बाद भी, उसे चार महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं किया गया और वास्तव में, एसआई राजेश कुमार ने उसे गिरफ्तार नहीं

किया और अगले अनुसंधान अधिकारी एएसआई रघबीर सिंह ने 24.6.2005 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। अपीलकर्ता का नाम 7.1.2005 को एफआईआर में दर्ज किया गया था, लेकिन फिर भी एसआई राजेश कुमार को उसको अनुसंधान में भी शामिल नहीं किया और उससे पूछताछ भी नहीं की, उसे गिरफ्तार करने की बात तो दूर रही। और इसलिए, माया देवी और बिरमा देवी के बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता जिस तरह से एसआई राजेश कुमार शुरू से ही अनुसंधान कर रहे थे।"

17. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर इस प्रकार से सहमति व्यक्त की है:

(1) अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है, जो गांव का सरपंच होने के नाते एक प्रभावशाली व्यक्ति था।

(II) ओंकार सिंह (पीडब्लू.8) एक स्वतंत्र गवाह थे और उसकी गवाही की अवहेलना करने का कोई आधार नहीं था।

(iii) आबादी घटनास्थल से कुछ दूरी पर थी। इसलिए, राज-मृतक और उसके बाद माया देवी (पीडब्लू.3) द्वारा मचाया गया शोर और रोना किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका।

(iv) मृतक द्वारा अपीलार्थी को भैंस की बिक्री के प्रतिफल के रूप में 47,000/- रुपये की राशि का भुगतान न करने बाबत् बचाव पक्ष द्वारा आरोप को गलत साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें अपील में कोई बल नहीं दिखता, जिसमें मेरिट की कमी है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

19. मामले को छोड़ने से पहले, हम इस मामले को हरियाणा राज्य के प्रशासन के ध्यान में लाना आवश्यक समझते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के द्वारा भी 7.1.2005 को पुलिस स्टेशन, सदर दादरी के SHO रहे श्री राजेश कुमार द्वारा की गई अनुचित जांच के संबंध में कुछ गंभीर निष्कर्ष भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन प्रशासन को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं, और हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों ने इतना उदासीन रवैया अपनाया है, जहां एक असहाय तलाकशुदा महिला के साथ ऐसा हुआ है।जहां पर एक विधवा महिला की हत्या की गई है और उसकी विधवा मां न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन प्रशासन ने गहरी नींद से जागना जरूरी नहीं समझा। हम हरियाणा राज्य के विद्वान मुख्य सचिव से मामले की

जांच करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का अनुरोध करते हैं। फैसले की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा सीधे मुख्य सचिव, हरियाणा को भेजी जाए।

के.के.टी. अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक इंद्रजीत पंवार , (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।